27/11/2017 (R) 338

hindustan times

CAG: Haryana agricultural varsity functioning with 45% teaching staff

Pawan Sharma

LISTS SHORTCOMINGS IN FINANCIAL AND MANPOWER MGMT AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AT THE HISAR-BASED VARSITY

CHANDIGARH: Haryana Agricultural University (HAU) has been reeling under shortage of 55% teaching and 41% non-teaching staff, while hostels of the university campus lacked basic amenities, according to Comptroller and Auditor General (CAG) of India.

In the performance audit (2017-18 fiscal) of the university presented in Haryana assembly on Tuesday, the CAG has brought out deficiencies in financial and manpower management and infrastructure development of the university.

The Hisar-based Haryana Agricultural University was set up in 1970. It was renamed as Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University in October 1991.

Citing example of lack in financial management, the CAG said grants totalling ₹3.12 crore were lying unspent in the university as "source and purpose" for which the funds were received were unknown. Not just this, temporary advances of ₹22.22 crore remained unadjusted.

The hostels of the university campus lacked basic amenities and the condition of Brahmsarovar hostel located at Kaul was very poor.

As many as 166 research projects were funded by other agencies, of which only 49 projects were completed.

On one hand the tissue culture laboratory was non-functional in the absence of specialised scientist, on the other, there was shortfall in enrolment in PG diploma and MBA courses ranging between 40% and 56%.

The CAG has said that only 44% and 50% cultivable land of Ram Dhan Singh seeds farm was utilised during kharif and rabi seasons. The kharif and rabi season crops had failed in the absence of irrigation arrangements despite availability of funds.

The University didn't propagate new crop varieties through Front Line Demonstrations (FLD) in a large number of new varieties. "On the other hand, FLDs were conducted on old varieties," the CAG has said, pointing out community radio stations were not established in six Krishi Vigyan Kendras even as ₹1.18 crore were released in 2011-13.

hindustantimes

2017-18 REPORT

CAG flags risk of substandard drugs

HT Correspondent
letters.hd@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The risk of manufacturing, distribution and sale of substandard drugs was high in Haryana in 2017-18 financial year, the Comptroller and Auditor General (CAG) of India has said.

The CAG had done audit of collection of samples and laboratory analysis of medicines in Ambala, Kurukshetra and Panchkula districts.

The audit brought to the fore that out of total 1,846 licensee units, samples were drawn from only 314 units, while 1,532 units remained unchecked. The sample analysis reports in case of 53.45% samples were issued after a delay of more than six months, it said.

And where sample didn't match quality standards, the action for recalling and issuing alert was initiated after an inordinate delay. "This was fraught with risk of consumption of substandard drugs by public," the CAG has said.

Also the destruction of substandard drugs was not monitored and subsequent batches were not checked. "Risk of manufacturing, distribution and sale of substandard drugs was high with serious implications for health and even lives of general public," the CAG audit says.

The procedure followed for local purchase of medicines "was not uniform and lacked transparency" and there were shortcomings in procurement of medicines and equipment, the CAG report presented to the Haryana Vidhan Sabha on Tuesday said.

OTHER ISSUES

- Haryana Shahri Vikas Pradhikaran irregularly allotted additional road-work to the "same contractor" by enhancing value of contract from ₹10 crore to ₹52 crore instead of calling for fresh tenders.
- Government deposited funds for making payment to landowners for construction of Rohtak-Meham-Hansi railway line after a delay of 508 days. This resulted in extra interest payment of ₹26.2 crore
- 29 girl hostels constructed at a cost of ₹47 crore lying unoccupied.

Bhaskar News

कैग रिपोर्ट: खनन, बिजली निगम समेत कई विभागों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

Ambala News - भास्कर न्यूज | राजधानी हरियाणा कैग की रिपोर्ट में खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। सबसे...

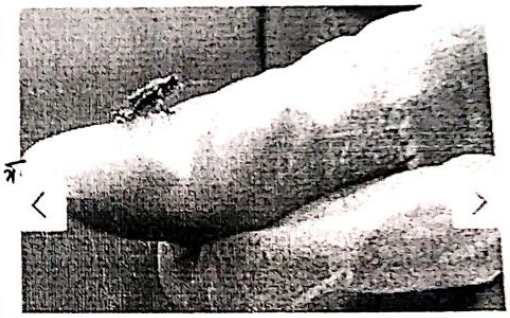
Bhaskar News Network Nov 27, 2019, 07:25 AM IST



भास्कर न्यूज | राजधानी हरियाणा

कैग की रिपोर्ट में खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। सबसे ब
बात यह है कि ठेकेदारों ने खनन में इस कदर मनमानी बरती कि इससे यमुना नदी
प्रवाह ही बदल गया। ठेकेदारों पर आरोप है कि नदी के प्रवाह में बाधा बन गए और न
का प्रवाह बदल गया।

चयनित रेत और बोल्डर बजरी खदानों के भू-स्थानिक सर्वेक्षण से पता चला है कि खन
योजनाओं में दिए गए खनक स्थलों के को-आर्डिनेट साइट निरीक्षण पर दर्शाए को
आर्डिनेट से भिन्न थे। खनन ठेकेदारों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस 24.36 करोड़



आज का राशिफल

dd-mm-yy

मेष वृष मिथुन कर्क

Next Stories

332

लापरवाही उजागर हुई है। सरकार ने खदान और खनिज विकास, पुनउद्धार पुनर्वास निधि में अपने हिस्से के 17.70 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए। जबकि 4.61 करोड़ रुपए का ब्याज क्रेडिट नहीं किया।

खदान और खनिज विकास की राशि न विभाग और न ठेकेदारों ने करवाई जमा

48 ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं

विभाग ने खदान और खनिज विकास एवं पुनर्वास निधिमि में 49.30 करोड़ रुपए की राशि जमा न कराने वाले 48 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इन ठेकेदारों की तरफ 17.44 करोड़ रुपए भी बकाया था। यही नहीं संविदा राशि 808.21 करोड़ रुपए जमा न कराने वाले 84 ठेकेदारों में से सरकार ने 69 के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इन पर करीब 347 करोड़ रुपए ब्याज के बकाया हैं।

माल ढोने वाले वाहन मालिकों ने नहीं दी राशि

रिपोर्ट में उल्लेख किया कि वर्ष 2016-17 के दौरान माल ढोने वाले 1584 वाहन मालिकों ने माल कर जमा नहीं कराया। इनसे 1.62 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की गई। इन पर 61.33 लाख रुपए ब्याज भी बकाया था। यही नहीं माल ढोने वाले 1305 वाहन मालिकों ने 2015-16 व 2016-17 के दौरान टोकन टैक्स जमा नहीं कराया, इससे 18.42 लाख रुपए की वसूली नहीं हुई। इन पर 36.84 लाख रुपए की पेनल्टी भी बकाया थी।

खनन ठेकेदारों ने बदला यमुना नदी का प्रवाह, स्टांप शुल्क के 24 करोड़ फंसे, 147 करोड़ के राजस्व का भी नुकसान

ईंट-भट्ठों के 181 मामलों में रॉयल्टी जमा नहीं: रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 4139 ईंट भट्ठा स्वामियों में से 181 मामलों में रॉयल्टी एवं अतिरिक्त रॉयल्टी के तौर पर 0.53 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए। इन पर 0.24 करोड़ रुपए ब्याज भी बकाया था।

लापरवाही: कम सिक्योरिटी के चलते निगम पर पड़ी दोगुनी मार

बिजली वितरण कंपनियों की लापरवाही के चलते निगमों को दोहरा नुकसान हुआ है। उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अग्रिम उपभोग राशि नहीं जमा करवाने से 1050 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। निगम उपभोक्ताओं से 935 करोड़ 91 लाख रुपए अग्रिम राशि के तौर पर वसूलने में भी विफल रहे। बिजली निगमों को अतिरिक्त ब्याज के तौर पर 122 करोड़ 5 लाख रुपए की चपत लगी। यह खुलासा विधानसभा में रखी कैग रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में 2013 से 2016 के दौरान निगमों को सी एंड टी लॉस के चलते 2703 करोड़ 69 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। निगमों ने सी एंड टी लॉस में सुधार किया। हरियाणा राज्य



राजोखेड़ी स्कूल में मनाया संविधान दिवस



लाई कृष्णा स्कूल : संविधान दिवस मनाया



बाबा अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस 6 को



मोहड़ा में कपड़ा फैक्टरी के गोदाम में भीषण आग, आधी रात तक भी न बुझी

दैनिक भास्कर — एजेंसियों को रोज 3.75 लाख का जुर्माना, फिर भी नहीं उठ रहा कूड़ा

दैनिक भास्कर — शहजादपुर, साहा और नारायणगढ़ ब्लॉक सक्षम-2 में हुए धराशायी

दैनिक भास्कर — बसपा नेता मदन लाल से जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर ठगे 3 लाख

दैनिक भास्कर — ओलावृष्टि व 15 एमएम बारिश से 7 डिग्री गिरा तापमान, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी घटकर 156 पर पहुंचा

(B) 33

कृषि : कम वसूली से 15 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान

कृषि पंप सेट मीटर वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभारों एवं नियत प्रभारों की कम वसूली हुई। मीटर किराए के कम प्रभारण के कारण निगमों को 15 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। मार्च-2018 तक बिजली कंपनियों ने एचईआरसी द्वारा निर्धारित संग्रहण दक्षता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया था। यही नहीं मार्च-2014 में यह बकाया 4460 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो अब मार्च-2018 में बढ़कर 7332 करोड़ 70 लाख पहुंच गया। कंपनी ने बिजली के ट्रांसफार्मर के तेल की खरीद ओपन टेंडर की बजाय लिमिटेड टेंडर से की। इससे निगम को 5 करोड़ 34 लाख रुपए अतिरिक्त खर्चने पड़े। निगम द्वारा खरीदे गए बिजली उपकरणों का इस्तेमाल भी इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि एनएबीएल सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट हासिल करने में देरी की गई। इससे कंपनी का 198 करोड़ 54 लाख से अधिक का सामान इस्तेमाल नहीं हो पाया।

बजट नहीं किया खर्च

हिसार कृषि विवि में मिलीं खामियों से योग्यता हुई कमजोर

कैग की रिपोर्ट ने हिसार के चौधरी चरण कृषि विश्विविद्यालयों की खामियां भी उजागर की हैं। जिस प्रकार खामियां सामने आई हैं, उससे विश्विविद्यालय अपने उद्देश्य प्राप्त करने की योग्यता को कमजोर किया है। 3.12 करोड़ रुपए अनुदान में मिले विवि ने खर्च ही नहीं किए। इसी प्रकार यहां पर पीजी डिप्लोमा 40 और एमबीए कोर्स में 56 फीसदी के बीच रही है। हाल यह है कि 55 प्रतिशत शैक्षणिक स्टाफ और 41 प्रतिशत गैर शैक्षणिक स्टाफ की कमी मिली। दो हॉस्अलों का रखरखाव खराब मिला। विशेषज्ञ वैज्ञानिक न होने की वजह से टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला सक्रिय नहीं है। 100 अनुसंधान परियोजनाओं में केवल 49 ही पूरी हुई मिली। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रामधन सिंह बीज फॉर्म की केवल 44 प्रतिशत और 50 प्रतिशत खेमी योग्य भूमि का प्रयोग भी नहीं किया गया।

2.1.6.2
P-12
2.1.7.2
P-13,14
2.1.8.2
P-22
2.1.9.1
P-31

इधर... दवाइयों की जांच पर सवाल

1846 मेडिकल स्टोर में सिर्फ 314 से ही लिए गए सैंपल

प्रदेश में दवाइयों की जांच कैसे और कितनी देरी से हो रही है, इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। दवाइयों की जांच रिपोर्ट आने तक लोग इन्हें निगल चुके थे। कैग ने इस देरी पर स्पष्ट कहा है कि यह लोगों के लिए जोखिम भरा था। रिपोर्ट के अनुसार तीन जिलों पंचकूला, अम्बाला और कुरूक्षेत्र में दवाओं के नमूनों के संग्रहण एवं प्रयोगशाला विश्लेषण की जांच में पाया कि 1846 लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर में से केवल 314 के नमूने लिए गए।

3.5.1
P-58,59

TIO

328

THE TIMES OF INDIA, CHANDIGARH | MOHALI | PANCHKULA | PATIALA | AMBALA
WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2019

Lax mining dept let contractors rob it of ₹1,476cr, reveals CAG

Report Says No Or Delayed Payment Led To Losses

Manvir.Saini@timesgroup.com

Chandigarh: Unscrupulous contractors took benefit of the lax management of the Haryana mining department and caused revenue loss of Rs 1,476.21 crore to the state in the financial year ending March 2018 alone, the Comptroller and Auditor General (CAG) has revealed.

This is sure to cause embarrassment to Manohar Lal Khattar-led BJP government, which fought the recent elections on the plank of good governance and barely managed to retain its hold on the power. Nayab Singh Saini, who held the mining and geology department portfolio in the last government, was elected as Kurukshetra MP in May. He was MLA from Naraingarh assembly constituency, one of the most mineral-rich areas of the state.

The CAG report, which pointed out how delayed and even non-payment of security deposits and royalty resulted in the loss to state exchequers, was tabled in the Haryana assembly on Tuesday.

"Management and monitoring of the funds by the department was deficient. Delays in renewal of licences to operate stone crushers, cases of short or non-recovery of royalty, additional royalty and interest thereon from the brick kiln owners were also noticed. These resulted in a loss of Rs 1,476.21 crore revenue," the report reads.

A total of 77 out of 95 contractors executed the agreements after delays ranging between five and 891 days. The CAG report says that nine contractors did not execute the agreements at all. It quantified such loss at Rs 398 crore, along with the penal interest of Rs 347.63 crore.

The opposition had accused former ministers and their kin of cornering mining licences in Yamunanagar, Panchkula, Charkhi-Dadri, Mahendergarh and other districts of Haryana.

CAG pointed out that besides defaulting on payment of bid money or security, certain contractors did not even executed the contract deeds with the government which resulted into the loss of stamp duty worth Rs 23.20 crore.

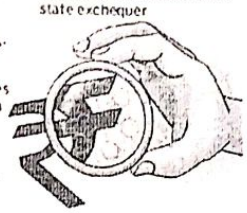
The firms that defaulted in executing the deed too were linked to influential politicians of the state and their companies are also accused of over exploiting the allotted zones for the purpose of mining of minor and major minerals.

According to norms, contractors or lessees are required to deposit security equal to 25% of the annual contract money or dead rent, out of which 10% shall be deposited as initial bid security at the fall of hammer and the balance 15% bid security shall be deposited before starting mining operations or before expiry of the period of 12 months from the date of issue of Letter of Intent, whichever is earlier.

CAG report says 59 contractors deposited balance bid security of Rs 122.02 crore with delay ranging between three and 854 days, while 11 contractors did not deposit the balance bid security of Rs 29.23 crore at all. The report also points out that the department not only failed to recover money but also did not take action against any of the defaulting contractor.

OTHER ISSUES IN REPORT

- Registering authorities incorrectly assessed 100 sale deeds of plots with an area less than 1,000 sq yards falling within municipal limits at rates fixed for agricultural land instead of residential land. This resulted in short levy of stamp duty and registration fees of ₹2.45 crore
- The registration authorities misclassified conveyance on sale as release deeds and levied stamp duty and registration fees of just ₹10,920 instead of ₹1.71 crore as per collector rate
- Irregular remission of stamp duty in 53 instruments of transfer deeds in favour of persons other than blood relations resulted in loss of revenue of ₹88.78 lakh to the state exchequer



HT

hindustantimes

'Mining contractors caused ₹1,500-crore loss in 2017-18'

Pawan Sharma
pawan.sharma@hindustantimes.com

CHANDIGARH : Haryana government suffered losses to the tune of Rs 1,476 crore due to numerous administrative lapses by the mines and geology department in 2017-18, according to the Comptroller and Auditor General (CAG) of India.

In its performance audit about the functioning of mines and geology department, the CAG has come across cases of either delayed or non-execution of agreements by the contractors and delayed/non-deposit of balance bid security.

"Delays in renewal of licences to operate stone crushers, cases of short/non-recovery of royalty...resulted in loss of Rs 1,476 crore," the CAG report that was tabled on the floor of Haryana assembly on Tuesday says.

Due to obstruction in river flow by sand miners, the river flow regime had changed, it says.

And the survey of selected sand and boulder/gravel mines revealed that there is mismatch between the coordinates of mining sites as given in mining plans and as observed on site inspection.

"As many as 77 of 95 contractors executed agreements after delay ranging between five and 891 days. Nine contractors didn't execute the agreements," the audit report says.

The contractors have to deposit security equal to 25% of the annual contract. While 10% security is deposited as initial bid security, the balance 15% is deposited before starting the mining operations.

But 59 contractors deposited balance bid security of Rs 132 crore with delay ranging between three and 854 days and 11 contractors didn't deposit balance bid security of Rs 29.28 crore, it points out.

The CAG has said department didn't initiate action against 48 contractors for short/non-deposit of Rs 49.30 crore in the mines and mineral development, restoration and rehabilitation fund.

RISE IN REVENUE RECEIPTS

In 2017-18 there was an increase in revenue receipts in Haryana over the previous year by Rs 10,198 crore (up by 19.43%).

The total revenue receipt of Haryana in 2017-18 was Rs 62,694.87 crore, up from Rs 52,496.82 crore in the 2016-17 fiscal.

Out of this, 80% (Rs 41,099.38 crore) was raised through tax revenue and non-tax revenue (Rs 9,112.85 crore), the balance 20% was received from the Union government as state's share.

CAG report in Haryana assembly brings out shortcomings in medicines and equipment procurement

The Comptroller and Auditor General of India's report for the year ending March 2018, tabled in the special session to mark Constitution Day, also said audit collection of samples and laboratory analysis of medicines in Ambala, Kurukshetra and Panchkula districts brought out that out of a total of 1,846 licensee units, samples were drawn from only 314 units and 1,532 units remained unchecked

3.5.1 P-58,59

INDIA

PTI
Chandigarh
Published on: November 27, 2019 6:44 IST



IMAGE SOURCE: FILE

CAG report in Haryana assembly brings out shortcomings in medicines and equipment procurement

The CAG report, tabled in the Haryana assembly on Tuesday, has brought out shortcomings in the procurement of medicines and equipment such as delay in the processing of the indents and award of rate contract to ineligible firms. The Comptroller and Auditor General of India's report for the year ending March 2018, tabled in the special session to mark Constitution Day, also said audit collection of samples and laboratory analysis of medicines in Ambala, Kurukshetra and Panchkula districts brought out that out of a total of 1,846 licensee units, samples were drawn from only 314 units and 1,532 units remained unchecked.

3.5 P-58,59

3.5 1-58,55

"Sample analysis reports in case of 53.45 per cent samples were issued after a delay of more than six months, and where sample was found not of standard quality, action for recalling and issuing alert was initiated with inordinate delay which was



TOP NEWS



ISRO to launch CARTOSAT-3, 13 other US satellites from Sriharikota today



Priyanka Chopra's pre-wedding anniversary surprise for husband Nick Jonas is the cutest. Watch video



The Pace of 2019: Indian fast bowlers wrap up best ever performance in a calendar year



Horoscope Today for November 27: Know astrological predictions for zodiac signs Pisces, Libra, Leo

322

fraught with the risk of consumption of substandard drugs by public," the report stated.

Destruction of substandard drugs was not monitored and subsequent batches were not checked, it said.

ADVERTISEMENT

[FP]

[EXTRAORDINARY NUMBER OF INTERFACES]

POWERED BY PLAYSTREAM


actress who inadvertently laid the foundation of #MeToo in India


RS Bhatti gets extension as Air India CVO



WhatsApp for Android, iOS: Top 5 features you should know about

"Risk of manufacturing, distribution and sale of substandard drugs was high with serious implications for health and even lives of general public," the report said.

3.6.2.4 / P-67

On the shortcomings in procurement of medicines, it said "there were shortcomings in procurement of medicines and equipment such as delay in processing of the indents, award of rate contract to ineligible firms, inadequate price comparison leading to extra expenditure of Rs 1.25 crore and non-levy of penalty of Rs 1.09 crore for non-supply of medicines".

Besides, availability of medicines at medical facilities was inadequate.

3.6.3.4 / P-71,72

"Procedure followed for local purchase of medicines was not uniform and lacked transparency. Further, equipment worth Rs 1.81 crore were lying unutilised at facilities," it said.

2.1 / P-7

The CAG, in its report, also rapped the Haryana Agricultural University at Hisar, as performance audit "brought out deficiencies in financial management, manpower management and infrastructure development which impaired the ability of HAU to achieve its overall objectives".

Highlighting "deficiencies" in working of various government departments, the report said though availability of urea was adequate yet there were systemic deficiencies.

3.1.2.1 / P-42

"Buffer stock of urea was not maintained and as against the target of procuring 38.79 lakh metric tonne urea, only 17.74 LMT urea was procured," it said.

3.9.4 / P-83

Information technology audit of e-procurement system brought out that the "e-procurement system database inducted in the state was fraught with risk of backend

You May Like Promoted Links

Avail Working Capital Loan | Lowest Interest Rates | Only at Paisabazaar
Paisabazaar.com

THEN and NOW: Krystle D'Souza, Devoleena and Rashami's old photos which will leave you shocked

Flights In India At Ridiculously Low Prices
TripsInsider

Holding multiple bank accounts? Then this is IMPORTANT for you

Pad(le) up for an exciting holiday in Australia
Tourism Australia

Shahid Kapoor hits the ball out of the park while prepping for Jersey remake. Watch

by Taboola

LATEST NEWS

320

interventions due to non-segregation of duties between data administrator and system administrator".

"Undue favour" in granting licences by the Town and Country Planning Department to two colonisers without assessing financial adequacy led to outstanding government dues of Rs 180.58 crore, it said.

Besides, there were instances of non-initiation of action against defaulters, inadequate efforts for auction of 24,355 unalloted properties in developed sectors hampered the revenue generation of Haryana Shahri Vikas Pradhikaran or the state's urban development authority.

Also, allotment of works by the Pradhikaran without acquisition of land and failure to ensure availability of encumbrances free land for the projects, the master water supply projects in Gurugram and Sonipat remained incomplete rendering expenditure of Rs 300.76 crore idle and resulted in blockade of Rs 26.35 crore on pipes yet to be laid, the CAG report said.

Procurement of buses with higher technical specifications, without upgrading the workshop facilities/technical skills of the mechanics and non-arrangement of annual maintenance contract, led to underutilization of 317 buses out of 418 buses and consequent loss of Rs 48.81 crore.

The report also pointed out that total expenditure of Haryana state increased by 89 per cent from Rs 46,598 crore to Rs 88,190 crore during the period 2013-14 to 2017-18 while the revenue expenditure increased by 75 per cent from Rs 41,887 crore to Rs 73,257 crore during the same period.

"The revenue expenditure constituted 75 to 92 per cent of the total expenditure while capital expenditure was 7 to 15 per cent during the period from 2013-14 to 2017-18," it said.

Also Read: Rahul, Priyanka to meet Chidambaram at Tihar on Nov 27

Also Read: Emergency declared for GoAir flight between Mumbai and Lucknow with 182 on-board

HARYANA ASSEMBLY CAG REPORT


decide at the floor test


Priyanka Chopra's pre-wedding anniversary surprise for husband Nick Jonas is the cutest. Watch video

INDIATV Chris Gayle takes 'break', says no to three-match ODI series against India

INDIATV The Pace of 2019: Indian fast bowlers wrap up best-ever performance in a calendar year

Discover the most sought after investment destination in NCR

Sobha Limited, Gurgaon | Sponsored

Personal Loans Up to 99 Lakhs for People Earning 25K INR+

Paisabazaar.com - India' Top Finance Portal | Sponsored

The Best Beaches In Southern Thailand

CNN International with Mastercard | Sponsored

Business Standard

CAG report in Hry assembly brings out shortcomings in medicines and equipment procurement

Press Trust of India | Chandigarh
Last Updated at November 26, 2019 23:20 IST

ALSO READ

J&K announces implementation of e-procurement policy, issues guidelines

Key panel to suggest changes in defence procurement policy to check delays

Token system will ensure transparency in paddy procurement:

Panel reviewing procurement policy framework to come out with new versions of DPP, DPM by Mar 2020

Number of sellers on govt's e-commerce platform

The CAG report, tabled in the Haryana assembly on Tuesday, has brought out shortcomings in the procurement of medicines and equipment such as delay in the processing of the indents and award of rate contract to ineligible firms.

The Comptroller and Auditor General of India's report for the year ending March 2018, tabled in the special session to mark Constitution Day, also said audit collection of samples and laboratory analysis of medicines in Ambala, Kurukshetra and Panchkula districts brought out that out of a total of 1,846 licensee units, samples were drawn from only 314 units and 1,532 units remained unchecked.

3.5.1
P-58,5

"Sample analysis reports in case of 53.45 per cent samples were issued after a delay of more than six months, and where sample was found not of standard quality, action for recalling and issuing alert was initiated with inordinate delay which was fraught with the risk of consumption of substandard drugs by public," the report stated.

Subscribe to insights at just Rs 149 per month

Subscribe Now >

90%
www.ecg
intraday

Destruction of substandard drugs was not monitored and subsequent batches were not checked, it said.

"Risk of manufacturing, distribution and sale of substandard drugs was high with serious implications for health and even lives of general public," the report said.

On the shortcomings in procurement of medicines, it said "there were shortcomings in procurement of medicines and equipment such as delay in processing of the indents, award of rate contract to ineligible firms, inadequate price comparison leading to extra expenditure of Rs 1.25 crore and non-levy of penalty of Rs 1.09 crore for non-supply of medicines".

Besides, availability of medicines at medical facilities was inadequate.

"Procedure followed for local purchase of medicines was not uniform and lacked transparency. Further, equipment worth Rs 1.81 crore were lying unutilised at facilities," it said.

The CAG, in its report, also rapped the Haryana Agricultural University at Hisar, as performance audit "brought out deficiencies in financial management, manpower management and infrastructure development which impaired the ability of HAU to achieve its overall objectives.".

Highlighting "deficiencies" in working of various government departments, the report said though availability of urea was adequate yet there were systemic deficiencies.

"Buffer stock of urea was not maintained and as against the target of procuring 38.79 lakh metric tonne urea, only 17.74 LMT urea was procured," it said.

Information technology audit of e-procurement system brought out that the "e-procurement system database inducted in the state was fraught with risk of backend interventions due to non-segregation of duties between data administrator and system administrator".

"Undue favour" in granting licences by the Town and Country Planning Department to two colonisers without assessing financial adequacy led to outstanding government dues of Rs 180.58 crore, it said.

Besides, there were instances of non-initiation of action against defaulters, inadequate efforts for auction of 24,355 unalloted properties in developed sectors hampered the revenue generation of Haryana Shahri Vikas Pradhikaran or the state's urban development authority.

Also, allotment of works by the Pradhikaran without acquisition of land and failure to ensure availability of encumbrances free land for the projects, the master water supply projects in Gurugram and Sonipat remained incomplete rendering expenditure of Rs 300.76 crore idle and resulted in blockade of Rs 26.35 crore on pipes yet to be laid, the CAG report said.

Procurement of buses with higher technical specifications, without upgrading the workshop facilities/technical skills of the mechanics and non-arrangement of annual maintenance contract, led to underutilization of 317 buses out of 418 buses and consequent loss of Rs 48.81 crore.

The report also pointed out that total expenditure of Haryana state increased by 89 per cent from Rs 46,598 crore to Rs 88,190 crore during the period 2013-14 to 2017-18 while the revenue expenditure increased by 75 per cent from Rs 41,887 crore to Rs 73,257 crore during the same period.

"The revenue expenditure constituted 75 to 92 per cent of the total expenditure while capital expenditure was 7 to 15 per cent during the period from 2013-14 to 2017-18," it said.

(This story has not been edited by Business Standard staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

Subscribe to insights at just Rs 149 per month
Subscribe Now ›

The Week

CAG report in Hry assembly brings out shortcomings in medicines and equipment procurement

PTI November 26, 2019 23:26 IST

Chandigarh, Nov 26 (PTI) The CAG report, tabled in the Haryana assembly on Tuesday, has brought out shortcomings in the procurement of medicines and equipment such as delay in the processing of the indents and award of rate contract to ineligible firms.

The Comptroller and Auditor General of India's report for the year ending March 2018, tabled in the special session to mark Constitution Day, also said audit collection of samples and laboratory analysis of medicines in Ambala, Kurukshetra and Panchkula districts brought out that out of a total of 1,846 licensee units, samples were drawn from only 314 units and 1,532 units remained unchecked.

"Sample analysis reports in case of 53.45 per cent samples were issued after a delay of more than six months, and where sample was found not of standard quality, action for recalling and issuing alert was initiated with inordinate delay which was fraught with the risk of consumption of substandard drugs by public," the report stated.

Destruction of substandard drugs was not monitored and subsequent batches were not checked, it said.

"Risk of manufacturing, distribution and sale of substandard drugs was high with serious implications for health and even lives of general public," the report said.

On the shortcomings in procurement of medicines, it said "there were shortcomings in procurement of medicines and equipment such as delay in processing of the indents, award of rate contract to ineligible firms, inadequate price comparison leading to extra expenditure of Rs 1.25 crore and non-levy of penalty of Rs 1.09 crore for non-supply of medicines".

Besides, availability of medicines at medical facilities was inadequate.

"Procedure followed for local purchase of medicines was not uniform and lacked transparency. Further, equipment worth Rs 1.81 crore were lying unutilised at facilities," it said.

The CAG, in its report, also rapped the Haryana Agricultural University at Hisar, as performance audit "brought out deficiencies in financial management, manpower management and infrastructure development which impaired the ability of HAU to achieve its overall objectives.".

Highlighting "deficiencies" in working of various government departments, the report said though availability of urea was adequate yet there were systemic deficiencies.

"Buffer stock of urea was not maintained and as against the target of procuring 38.79 lakh metric tonne urea, only 17.74 LMT urea was procured," it said.

Information technology audit of e-procurement system brought out that the "e-procurement system database inducted in the state was fraught with risk of backend interventions due to non-segregation of duties between data administrator and system administrator".

"Undue favour" in granting licences by the Town and Country Planning Department to two colonisers without assessing financial adequacy led to outstanding government dues of Rs 180.58 crore, it said.

Besides, there were instances of non-initiation of action against defaulters, inadequate efforts for auction of 24,355 unalloted properties in developed sectors hampered the revenue generation of Haryana Shahri Vikas Pradhikaran or the state's urban development authority.

Also, allotment of works by the Pradhikaran without acquisition of land and failure to ensure availability of encumbrances free land for the projects, the master water supply projects in Gurugram and Sonipat remained incomplete rendering expenditure of Rs 300.76 crore idle and resulted in blockade of Rs 26.35 crore on pipes yet to be laid, the CAG report said.

Procurement of buses with higher technical specifications, without upgrading the workshop facilities/technical skills of the mechanics and non-arrangement of annual maintenance contract, led to underutilization of 317 buses out of 418 buses and consequent loss of Rs 48.81 crore.

The report also pointed out that total expenditure of Haryana state increased by 89 per cent from Rs 46,598 crore to Rs 88,190 crore during the period 2013-14 to 2017-18 while the revenue expenditure increased by 75 per cent from Rs 41,887 crore to Rs 73,257 crore during the same period.

"The revenue expenditure constituted 75 to 92 per cent of the total expenditure while capital expenditure was 7 to 15 per cent during the period from 2013-14 to 2017-18," it said.

PTI SUN ANB

ANB

310

AMAR UJALA

कैग रिपोर्ट: हरियाणा में खनन माफिया बेलगाम, विभागीय लापरवाही से लगी 1476 करोड़ की चपत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 27 Nov 2019 10:35 AM IST



फाइल फोटो

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई है। मंगलवार को कैग की 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी गई। इसमें अनेक अनियमितताओं को उजागर किया गया है। सरकारी खर्च बढ़ा है, आमदनी कम हुई है और खनन माफिया व ठेकेदार पूरी तरह से बेलगाम हैं। सरकारी विभागों के लापरवाही बरतने से सरकारी खजाने को राजस्व में बड़ी चपत लगी है।

हरियाणा में नियमों के विरुद्ध खनन को कैग ने उजागर किया है, साथ ही ये भी बताया है कि कई जगह खनन माफिया ने नदी का बहाव तक बदल दिया है। खनन विभाग की लापरवाही के कारण सरकार को 1476 करोड़ रुपये की चपत लगी है। कैग ने खनन के लिए आवंटित स्थलों का निरीक्षण भी किया है। जिसमें पाया गया कि आवंटित स्थानों के बजाए माफिया ने दूसरी जगह खनन किया। ठेकेदारों के प्रति विभागों का रवैया ढुलमुल रहा है।

खनन विभाग ने खदान और खनिज विकास एवं पुनर्वास निधि में 49 करोड़ 30 लाख रुपये नहीं जमा करवाने वाले 48 ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। टेंडर राशि जमा नहीं करवाने वाले 84 में से 69 ठेकेदारों के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इन ठेकेदारों पर बकाया 347 करोड़ रुपये नहीं वसूले गए। रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल व्यय 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 89 प्रतिशत बढ़कर 46598 करोड़ से बढ़कर 88190 करोड़ हो गया।

राजस्व व्यय में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 41887 करोड़ से बढ़कर 73257 करोड़ पहुंच गया। कुल व्यय में राजस्व व्यय का भाग 75 से 91 प्रतिशत था, जबकि पूंजीगत व्यय सात से 15 प्रतिशत। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार वर्ष 2013 से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करने में विफल रही। इससे अगस्त 2013 से प्राप्त हुई 681 शिकायतों का निपटान नहीं हो पाया। कृषि पंपसेट मीटर वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभारों एवं नियत प्रभारों की कम वसूली हुई।

मीटर किराए के कम प्रभारण के कारण निगमों को 15 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। मार्च-2018 तक बिजली कंपनियों ने एचईआसी के निर्धारित संग्रहण दक्षता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया था। मार्च-2014 में यह बकाया 4460 करोड़ 18 लाख रुपये था, जो अब मार्च-2018 में बढ़कर 7332 करोड़ 70 लाख पहुंच चुका है।

बिजली कंपनियों की लापरवाही से 1050 करोड़ का चूना

बिजली वितरण कंपनियों की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अग्रिम उपभोग राशि नहीं जमा कराई जा सकी, जिस कारण 1050 करोड़ रुपये का चूना लगा है। बिजली निगमों के उपभोक्ताओं से कंपनियां 935 करोड़ 91 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर वसूलने में विफल रही।

इस वजह से निगमों को अतिरिक्त ब्याज के तौर पर 122 करोड़ 5 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2016 के दौरान निगमों को सीएंडटी लॉस (तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां) के चलते 2703 करोड़ 69 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। बाद में निगमों ने इन हानियों में कुछ सुधार किया है।

306

यूरिया खाद के बफर स्टाक का रखरखाव उचित नहीं

यूरिया के बफर स्टाक का रखरखाव उचित तरीके से न करने पर कैग ने सवाल खड़े किए हैं। 38.79 लाख टन यूरिया खरीद का लक्ष्य था, लेकिन खरीद महज 17.74 लाख टन की गई। 6367 नमूनों के संग्रहण के लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए और केवल 4709 नमूने लिए गए। जिन डीलरों के नमूने सही नहीं थे उनमें से केवल 9 पर कार्रवाई की गई, जबकि 37 डीलरों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई।

P-3.1.2.1
P-42

अंबाला, कुरुक्षेत्र व पंचकूला में दवाइयों के सेंपल नहीं

कैग ने हरियाणा के तीन जिलों कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला में दवाओं के नमूनों के संग्रहण एवं प्रयोगशाला विश्लेषण की जांच में पाया कि 1846 लाइसेंसधारी इकाईयों में से केवल 314 के नमूने लिए गए, जबकि 1532 इकाईयां बिना जांच के रह गई। 53.45 फीसदी नमूनों के मामलों में नमूना विश्लेषण रिपोर्ट छह माह से अधिक देरी से जारी की गई। लोगों के लिए इन दवाओं का उपयोग जोखिम भरा था। दवाओं की आर्पूति न करने के लिए कंपनियों पर 1.09 करोड़ रुपए जुर्माना नहीं लगाया गया।

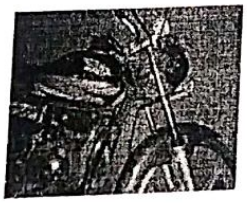
3.5
P-58,59

3.6.2.4
P-67

विज्ञापन

नए साल में करियर में एक नया मुकाम हासिल हो पाएगा कि नहीं? फाइनेंस के मामले में स्थिति कैसी रहने वाली है?, जानिये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से (https://www.amarujala.com/astrology-services-online?utm_campaign=astrology&utm_source=text_ad_widget&utm_medium=leads) Register Now!

Recommended



Chandigarh (/chandigarh) 27 नवंबर 2019

फतेहाबाद: ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा भिड़ी बाइक और दर्दनाक हादसे में गई तीन सगे भाइयों की जान (/haryana/fatehabad/three-brothers-died-in-road-accident-fatehabad-news-rtk5294912160?src=story-related)

Haryana: CAG finds shortcomings in medicine, equipment procurement

PRESS TRUST OF INDIA
CHANDIGARH, NOVEMBER 26

The report also pointed out that total expenditure of Haryana increased by 89 per cent from ₹46,598 cr to ₹88,190 cr during the period 2013-14 to 2017-18

IN A report tabled in Haryana assembly Tuesday, the The Comptroller and Auditor General (CAG) highlighted shortcomings in the procurement of medicines and equipment, such as delay in the processing of the indents and award of rate contracts to ineligible firms.

The CAG report for the year ending March 2018, tabled in the special session to mark Constitution Day, also said that audit collection of samples and laboratory analysis of medicines in Ambala, Kurukshetra and Panchkula districts showed that out of a total of 1,846 licensee units, samples were drawn from only 314 and 1,532 units remained unchecked.

"Analysis reports in case of 53.45 per cent samples were issued after a delay of more than six months...where sample was found not of standard quality, action for recalling and issuing alert was initiated with inordinate delay, which was fraught with the risk of consumption of substandard drugs by public," the report said.

Destruction of substandard drugs was not monitored and subsequent batches were not checked, it said.

"Risk of manufacturing, distribution and sale of substandard drugs was high with serious implications for health and even lives of general public," the report said.

It said there were shortcomings in procurement of medicines and equipment "such as delay in processing of the indents, award of rate contract to ineligible firms, inadequate price comparison leading to extra expenditure of Rs 1.25 crore and non-levy of penalty of Rs 1.09 crore for non-supply of medicines".

Besides, availability of medicines at medical facilities was inadequate. "Procedure followed for local purchase of medicines was not uniform and lacked transparency. Further, equipment worth Rs 1.81 crore were lying unutilised at facilities," it said.

The CAG, in its report, also rapped the Haryana Agricultural University at Hisar, for "deficiencies in financial management, manpower management and infrastructure development, which impaired the ability of HAU to achieve its overall objectives".

Highlighting "deficiencies" in working of various government departments, the report said though availability of urea was adequate yet there were systemic deficiencies. "Buffer stock of urea was not maintained and as against the target of procuring 38.79 lakh metric tonne urea, only 17.74 LMT urea was procured," it said.

Information technology audit of e-procurement system brought out that the "database inducted in the state was fraught with risk of backend interventions due to non-segregation of duties between data administrator and system administrator".

"Undue favour" in granting licences by the Town and Country Planning Department to two colonisers without assessing financial adequacy led to outstanding government dues of Rs 180.58 crore, it said.

Besides, there were instances of non-initiation of action against defaulters, inadequate efforts for auction of 24,365 unallotted properties in developed sectors hampered the revenue generation of Haryana Shahri Vikas Pradhikaran or the state's urban development authority.

Also, allotment of works by the Pradhikaran without acquisition of land and failure to ensure availability of encumbrances free land for the projects, the master water supply projects in Gurugram and Sonipat remained incomplete rendering expenditure of Rs 300.76 crore idle and resulted in blockade of Rs 26.35 crore on pipes yet to be laid, the CAG report said.

Procurement of buses with higher technical specifications, without upgrading the workshop facilities/technical skills of the mechanics and non-arrangement of annual maintenance contract, led to underutilization of 317 buses out of 418 buses and consequent loss of Rs 48.81 crore.

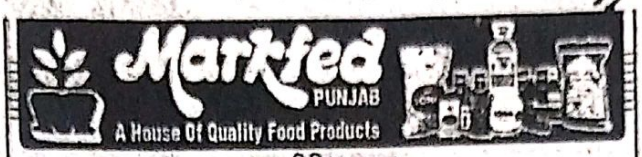
The report also pointed out that total expenditure of Haryana state increased by 89 per cent from Rs 46,598 crore to Rs 88,190 crore during the period 2013-14 to 2017-18 while the revenue expenditure increased by 75 per cent from Rs 41,887 crore to Rs 73,257 crore during the same period.

"The revenue expenditure constituted 75 to 92 per cent of the total expenditure while capital expenditure was 7 to 15 per cent during the period from 2013-14 to 2017-18," it said.

Punjab Kesari

बिजली निगम को 1050 करोड़ की चपत

चंडीगढ़, 26 नवम्बर (बंसल/पांडेय): हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों की हीलाहवाली के कारण निगम को करीब 1050 करोड़ का नुक्सान झेलना पड़ा। बताया गया कि निगम उपभोक्ताओं से 935 करोड़ 91 लाख रुपए अग्रिम राशि के तौर पर वसूलने में पीछे रहे। इस कारण निगमों को अतिरिक्त ब्याज के तौर पर 122 करोड़ 5 लाख की चपत लगी। यह खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है। विधानसभा सत्र में रखी कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 से 2016 दौरान बिजली निगमों को कई तरह से हानि झेलनी पड़ी।



अल्प निविदा सूचना

एतद् द्वारा पंजीकृत श्रम व निर्माण समितियों, पंजाब तथा पंजीकृत ठेकेदारों जिनके पास लोनिवि (बी एंड आर)/कैलोनिवि/एमईएस/रेलवे विभाग की सूचीबद्धता हो, पैन नम्बर, जीएसटी नं., ईपीएफ नं. तथा श्रम विभाग के श्रम पंजीकरण चार्कों से निम्नलिखित कार्य के लिए मोहरबंद प्रतिष्ठित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 02.12.2019 को प्रातः 11.00 बजे जारी किए जाएंगे तथा दोपहर 12.00 बजे प्राप्त किए जाएंगे तथा वे उसी दिन दोपहर 12.30 बजे एक्सियन (मुख्यालय), मार्कफैड प्लाट नं. 4, सैक्टर 35बी चंडीगढ़ के कार्यालय में खोली जाएंगी। यदि सहकारी समितियों की ओर से दो वैध निविदाएं प्राप्त नहीं होती हैं तभी अन्य ठेकेदारों की निविदाएं उसी समय और उसी दिन पार्टियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। समितियों के संबंध में मोहर राशि आरसीएस, पंजाब के निर्देशानुसार जमा की जाएगी। अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित मंडल में देखी जा सकती हैं। मार्कफैड बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा लागत	धरोहर राशि	समय सीमा
1.	फतेहगढ़ साहिब में बाबा मोती राम मेहर स्मारक गेट की मुरम्मत (सिविल कार्य)	(रु.) 244616/-	(रु.) 4900/-	10 दिन

(DPR/C-7931). कार्यकारी अभियंता (मु.), मार्कफैड, चंडीगढ़

पंजाब ग्रामीण जल व स्वच्छता सैक्टर सुधार प्रोजैक्ट
विश्व बैंक पोषित
बोलियों हेतु आमंत्रण

1. चेयरमैन जीपीडब्ल्यूएससी, गांव तिरक कर्मा (2 अदद) ब्लाक व जिला रूपनगर, कार्यकारी अभियंता, जलापूर्ति व स्वच्छता मंडल सं. 2, रूपनगर के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित करते हैं :-
   (i) पीआरडब्ल्यूएसएसआईपी/एनआरडीडब्ल्यूपी अधीन गांव तिरक कर्मा (2 अदद), ब्लाक व जिला रूपनगर हेतु प्रस्तावित जलापूर्ति स्कीम।
   विस्तृत बोली हेतु आमंत्रण जिसमें बोलियां जमा करने हेतु निर्देश एवं अन्य सभी संबंधित जानकारी शामिल है https://eproc.punjab.gov.in पर उपलब्ध है।
2. डाक्यूमैंटस हेतु बोली दस्तावेज इस वैबसाईट पर आनलाइन भी उपलब्ध है।
3. बोलियां जमा करने हेतु डैडलाइन 10.12.2019, 11.00 बजे है। पार्ट-1 बोलियां उसी दिन 15.00 बजे खोली जाएंगी।
4. बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों में वर्णित न्यूनतम पात्रता मापदंड नोट करने की सलाह दी जाती है। केवल वे बोलीदाता बोली दस्तावेजों में दिए निर्देशों अनुरूप बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
5. निविदा सूचना के किसी भी संशोधन (नों) को केवल उपरोक्त वैबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

ब्लाक पता : कार्यकारी अभियंता,
जलापूर्ति व स्वच्छता मंडल सं. 2,
तिरक्का स्कूल रोड, रूपनगर-140001
फोन नं. : 01881-222349
ई-मेल आईडी : division_rpnr@yahoo.co.in

कार्यकारी अभियंता,
जलापूर्ति व स्वच्छता मंडल सं. 2, रूपनगर

हुड्डा ने दिल्ली को विशाल हरियाणा व राजधानी बनाने का फैंका नया पार

चंडीगढ़, 26 नवम्बर (बंसल/पांडेय): नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संविधान दिवस के मौके पर 'संकल्प-पत्र' पर चर्चा दौरान नया पासा फैंकते हुए विशाल हरियाणा बनाने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि उनके पिता एवं बीर हुड्डा ने 2 अगस्त, 1949 को संविधान सभा में मामला रखा था कि पंजाब के 2 हिस्से होंगे और यू.पी. का एक हिस्सा काटकर विशाल हरियाणा बनाया जाएगा। इस विशाल हरियाणा की राजधानी दिल्ली को भी बनाने का प्रस्ताव था, जो अब तक सिरे नहीं चढ़ सका है। हुड्डा ने कहा कि पंजाब के 2 हिस्से का काम हो चुका लेकिन यू.पी. और दिल्ली का मुद्दा अभी बाकी है।



सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान का भरतपुर जिला भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी यू.पी. और भरतपुर जिले के लोगों की जीवन शैली हरियाणा से मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के लिए हरियाणा से 3 लोग चुने गए थे जिनमें पिता एवं बीर हुड्डा, जिनका जन्मदिवस भी है, निहाल सिंह तक्षक और ठाकुर दास भार्गव थे। इनमें से 2 के हस्ताक्षर भी संविधान में अंकित हैं। हुड्डा ने कहा कि संविधान निर्माण दौरान किसान एम.एस.पी. का मामला भी उठा जिसका उल्लेख पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी किया था के अलावा कांग्रेस और सत्ता कई सदस्यों ने भी एवं बीर हुड्डा के होने का उल्लेख किया।

हुड्डा ने चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा किया कमजोर : वि

गृह मंत्री अनिल विज ने 'वि हरियाणा' की मांग पर हुए कहा कि ने चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कम कर दिया है। इसके लिए जनता नहीं करेगी। पत्रकारों से बातचीत में ने कहा कि कांग्रेस की मांग से लोग भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं सदन में मह विवाद दौरान जब हुड्डा और वि बहसबाजी हो रही थी तो हुड्डा ने कि संविधान पर बोलने की बात हो है लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा। ने विधानसभा सदन में दिखे शब्द और इशारा करते हुए कहा कि यहां है कि सदन में या तो आओ मत न सच की बात करो।

मंत्री दलाल द्वारा धान घोटाले को क्लीन चि देने के बयान पर अभय ने जताई आपत्ति

चंडीगढ़, 26 नवम्बर (बंसल): इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने मंत्री जेपी दलाल के बयान पर कहा कि अभी तक अधिकारियों ने पड़ता को निरीक्षण रिपोर्ट सरकार को सौंपी नहीं है परंतु कृषि मंत्री ने घोटाला करने वालों को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि कोई धान घोटाला हुआ जिससे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। कहीं न कहीं बात जिन अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार उन अधिकारियों को स्टाक की जांच की जिम्मेवारी दी है।

(300)

The TRIBUNE

zens' responsibilities. said special aspect of the

Lapses cost Hry mines dept ₹1,476cr

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, NOVEMBER 26

The Comptroller and Auditor General (CAG) has detected a loss of Rs 1,476 crore in Haryana's Mines and Geology department due to irregularities in the execution of its projects.

The CAG report on the revenue sector of Haryana for 2017-18 was placed before the state Assembly on Tuesday.

In the mining department, the CAG observed losses on account "delayed or non-execution of agreements by the contractors, delayed or non-deposit of balance security, non-deposit of monthly instalments of contract money and interest thereon from the contractors".

Also, there was insufficient contribution to the Mines and Mineral Development, Restoration and Rehabilitation Fund by the contractors as well as by the government.

The CAG said 77 of the total 95 contractors "executed agreements after a delay ranging between five and 891 days and nine contractors did not execute the agreements".

CAG: IRREGULARITIES IN POWER UTILITIES TOO

The Comptroller and Auditor General (CAG) has also detected irregularities in the Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam, which caused a loss of ₹4,021 crore to the state exchequer

...fill...enders to get certificat

The Tribune

CAG finds gaps of ₹4K cr in DHBVN

BHARTESH SINGH THAKUR
TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, NOVEMBER 26

The Comptroller and Auditor General (CAG) has detected irregularities in the Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN), which caused a loss of ₹4,021 crore to the state exchequer.

The losses are on account of "avoidable burden of interest, avoidable payments and wasteful expenditure".

The CAG mentioned about the losses in its report submitted on public sector undertakings of Haryana for the year ending March 31, 2018, in the Assembly on Tuesday.

The report brought out that the DHBVN had to bear a loss of ₹2,703 crore from 2013 to 2016, as technical and commercial losses were more than what was prescribed by the Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC). The discom, however, achieved the required target in 2016-18.

The DHBVN recovered ₹935.91 crore less as additional advance consumption deposit from its consumers and, as a result, had to bear an avoidable interest burden of ₹122.05 crore on increased borrowings.

It allowed concession of ₹14.40 crore during 2005-06 to 2017-18 to women consumers in contravention of the provisions of the Electricity Act and tariff orders issued by the HERC from time to time.

The discom supplied excess power of 1,615 metered units to unmetered agriculture pump-set consumers, resulting in a loss of ₹18.90 crore.

The DHBVN couldn't achieve collection efficiency targets in the past five years, ending March 2018 as prescribed by the HERC. As a result, recoverable amount had increased from ₹4,460 crore in March 2014 to ₹7,332.70 crore in March 2018.

On the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN), the CAG pointed out that extra expenditure of ₹5.34 crore was incurred "on purchase of transformer oil by resorting to limited tender enquiry instead of open tenders".

The CAG also detected that the Haryana Power Purchase Centre suffered a loss of ₹2.72 crore as it didn't include any penal provision in an MoU with the Indian Renewable Energy Development Agency for charging interest "in case of delayed payment towards generation-based incentive claims"

₹5.15-CR REVENUE LOSS

Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited did not collect toll departmental-wise till the award of toll collection contract, resulting in a revenue loss of ₹5.15 crore.



HT

'Mining contractors caused ₹1,500-crore loss in 2017-18'

Pawan Sharma
pawan.sharma@hindustantimes.com

CHANDIGARH : Haryana government suffered losses to the tune of Rs 1,476 crore due to numerous administrative lapses by the mines and geology department in 2017-18, according to the Comptroller and Auditor General (CAG) of India.

In its performance audit about the functioning of mines and geology department, the CAG has come across cases of either delayed or non-execution of agreements by the contractors and delayed/non-deposit of balance bid security.

"Delays in renewal of licences to operate stone crushers, cases of short/non-recovery of royalty... resulted in loss of Rs 1,476 crore," the CAG report that was tabled on the floor of Haryana assembly on Tuesday says.

Due to obstruction in river flow by sand miners, the river flow regime had changed, it says.

And the survey of selected sand and boulder/gravel mines revealed that there is mismatch between the coordinates of mining sites as given in mining plans and as observed on site inspection.

"As many as 77 of 95 contractors executed agreements after delay ranging between five and 891 days. Nine contractors didn't execute the agreements," the audit report says.

The contractors have to deposit security equal to 25% of the annual contract. While 10% security is deposited as initial bid security, the balance 15% is deposited before starting the mining operations.

But 59 contractors deposited balance bid security of Rs 132 crore with delay ranging between three and 854 days and 11 contractors didn't deposit balance bid security of Rs 29.28 crore, it points out.

The CAG has said department didn't initiate action against 48 contractors for short/non-deposit of Rs 49.30 crore in the mines and mineral development, restoration and rehabilitation fund.

RISE IN REVENUE RECEIPTS

In 2017-18 there was an increase in revenue receipts in Haryana over the previous year by Rs 10,198 crore (up by 19.43%).

The total revenue receipt of Haryana in 2017-18 was Rs 62,694.37 crore, up from Rs 52,496.82 crore in the 2016-17 fiscal.

Out of this, 80% (Rs 41,699.38 crore) was raised through tax revenue and non-tax revenue (Rs 9,112.85 crore), the balance 20% was received from the Union government as state's share.

Missing 8-year-old boy found dead

HT Correspondent
letterschd@hindustantimes.com

ROHTAK : An 8-year-old boy, who was missing since November 19, was found dead at a room in the fields of his village Bhadhana, in Sonepat district, police said.

The boy has been identified as Sourya. He was the nephew of Lavesh Sharma, media consultant to former local bodies minister Kavita Jain.

In his complaint to the police, victim's father Mohan said his son was playing in the street outside his house when he went missing on November 19. "We lodged a missing complaint at Baroda police station. On Tuesday, police carried out a search operation with the help of dog squad. His body was found at a room built in the fields," he said.

A murder case has been registered against the unidentified persons and probe is on.

Dainik Jagran
STATE BUREAU

हावी रहा खनन माफिया नदियों का बदला बहाव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : विधानसभा के पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। सरकारी विभागों में जमकर लापरवाही बरती गई, जिस कारण सरकारी खजाने को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा है।

हरियाणा में खनन माफिया पूरी तरह से हावी है। कैग की रिपोर्ट में इस बात को खुलकर स्वीकार किया गया है। राज्य में नियमों के विरुद्ध खनन किया गया, जिस कारण कई जगह नदी का बहाव तक बदल गया। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में रखी गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि खनन विभाग की लापरवाही के चलते 1476 करोड़ रुपये की चपत सरकार को लगी है।

खनन योजनाओं के लिए अलाट साइट का निरीक्षण करते हुए कैग ने कहा है कि आवंटित साइट की बजाय दूसरी जगहों पर खनन किया गया था। कैग के अनुसार ठेकेदारों के प्रति सरकार का रवैया लचीला रहा। विभाग ने खदान और खनिज विकास एवं पुनर्वास निधि में 49 करोड़ 30 लाख रुपये नहीं जमा करवाने वाले 48 ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। टेंडर राशि जमा नहीं करवाने वाले 84 में से 69 ठेकेदारों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इन ठेकेदारों पर 347 करोड़ रुपये बकाया रहे।

पंचकूला, अंबाला व कुरुक्षेत्र में दवाइयों के सैंपल नहीं : कैग ने हरियाणा के तीन जिलों पंचकूला, अंबाला और कुरुक्षेत्र में दवाओं के नमूनों के संग्रहण एवं प्रयोगशाला विश्लेषण की जांच में पाया कि 1846 लाइसेंसधारी इकायों में से केवल 314 के नमूने लिए गए, जबकि 1532 इकाइयां बिना जांच के रह गईं। 53.45 फीसद नमूनों के मामलों में नमूना विश्लेषण रिपोर्ट छह माह से अधिक देरी से जारी की गई। लोगों द्वारा इन दवाओं का उपयोग जोखिम भरा था। दवाओं की आपूर्ति न करने के लिए कंपनियों पर 1.09 करोड़ रुपये जुर्माना नहीं लगाया गया। वहीं कैग रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2013 से प्राप्त हुई 681 शिकायतों का निपटान नहीं हो पाया।

खुलासा

- हरियाणा विधानसभा के पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट
- सरकारी विभागों में करोड़ों रुपये की अनियमितताएं उजागर

बिजली उपभोक्ताओं से नहीं वसूले 935 करोड़

राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अग्रिम उपभोग राशि नहीं जमा कराई जा सकी, जिस कारण 1050 करोड़ रुपये की चपत लगी है। बिजली निगमों के उपभोक्ताओं से कंपनियां 935 करोड़ 91 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर वसूलने में विफल रही। इस वजह से निगमों को अतिरिक्त ब्याज के तौर पर 122 करोड़ 5 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2016 के दौरान निगमों को सी एंड टी लॉस (तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां) के चलते 2703 करोड़ 69 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। बाद में निगमों ने इन हानियों में सुधार किया।

HT

birth anniversary of Dr Bhim Rao However, the scene got volatile House in smiles.

CAG: Haryana agricultural varsity functioning with 45% teaching staff

Pawan Sharma
• pawan.sharma@hindustantimes.com

LISTS SHORTCOMINGS IN FINANCIAL AND MANPOWER MGMT AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AT THE HISAR-BASED VARSITY

CHANDIGARH: Haryana Agricultural University (HAU) has been reeling under shortage of 55% teaching and 41% non-teaching staff, while hostels of the university campus lacked basic amenities, according to Comptroller and Auditor General (CAG) of India.

In the performance audit (2017-18 fiscal) of the university presented to Haryana assembly on Tuesday, the CAG has brought out deficiencies in financial and manpower management and infrastructure development of the university.

The Hisar-based Haryana Agricultural University was set up in 1970. It was renamed as Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University in October 1991.

Citing example of lack in financial management, the CAG said grants totalling ₹5.12 crore were lying unspent in the university as "source and purpose" for which the funds were received were unknown. Not just this, temporary advances of ₹22.22 crore remained unadjusted.

The hostels of the university campus lacked basic amenities and the condition of Brahmsarovar hostel located at Kaul was very poor.

As many as 100 research projects were funded by other agencies, of which only 49 projects were completed.

On one hand the tissue culture laboratory was non-functional in the absence of specialised scientist, on the other, there was shortfall in enrolment in PG diploma and MBA courses ranging between 40% and 56%.

The CAG has said that only 44% and 50% cultivable land of Ram Dhan Singh seeds farm was utilised during kharif and rabi seasons. The kharif and rabi season crops had failed in the absence of irrigation arrangements despite availability of funds.

The University didn't propagate new crop varieties through Front Line Demonstrations (FLD) in a large number of new varieties. "On the other hand, FLDs were conducted on old varieties," the CAG has said, pointing out community radio stations were not established in six Krishi Vigyan Kendras even as ₹1.18 crore were released in 2011-13.

Highlights

- The exterior and the interiors of the Haryana assembly were tastefully decorated with flowers to mark the session.
- At the very onset of the session, almost all the MLAs of the Congress were present, though only chief minister Manohar Lal Khattar and deputy chief minister Dushyant Chautala were seen on the treasury benches as others came a few minutes later.
- The voice of leader of opposition Bhupinder Singh Hooda choked as he read out obituary reference of his younger brother Dharmender Singh Hooda, saying "it is a greater hurt when a younger one leaves".
- The House plunged into laughter when several MLAs, especially the first-timers, began to raise their local problems during the discussions on the Constitution and did not stop despite objections by the speaker.
- Hooda stunned the House with his prank when he objected to an "impersonator occupying an MLA's seat". When Speaker asked who it was, Hooda asked speaker to look at the House sitting arrangement page which had picture of an MLA with black beard at seat No. 4 and then look at who was actually sitting there. Home minister Anil Vij, whose beard was fully white.
- Hooda said though he is entirely hopeful that an MLA from opposition was elected as deputy speaker, but he backed BJP's Ranbir Gangwa as he was a "good man".

2017-18 REPORT

CAG flags risk of substandard drugs

HT Correspondent
• letterschd@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The risk of manufacturing, distribution and sale of substandard drugs was high in Haryana in 2017-18 financial year, the Comptroller and Auditor General (CAG) of India has said.

The CAG had done audit of collection of samples and laboratory analysis of medicines in Ambala, Kurukshetra and Panchkula districts.

The audit brought to the fore that out of total 1,846 licensee units, samples were drawn from only 814 units, while 1,532 units remained unchecked. The sample analysis reports in case of 53.45% samples were issued after a delay of more than six months, it said.

And where sample didn't match quality standards, the action for recalling and issuing alert was initiated after an inordinate delay. "This was fraught with risk of consumption of substandard drugs by public," the CAG has said.

Also the destruction of substandard drugs was not monitored and subsequent batches were not checked. "Risk of manufacturing, distribution and sale of substandard drugs was high with serious implications for health and even lives of general public," the CAG audit says.

The procedure followed for local purchase of medicines "was not uniform and lacked transparency" and there were shortcomings in procurement of medicines and equipment, the CAG report presented to the Haryana Vidhan Sabha on Tuesday said.

OTHER ISSUES

- Haryana Shahri Vikas Pradhikaran irregularly allotted additional road-work to the "same contractor" by enhancing value of contract from ₹10 crore to ₹52 crore instead of calling for fresh tenders.
- Government deposited funds for making payment to landowners for construction of Rohtak-Meham-Hansi railway line after a delay of 508 days. This resulted in extra interest payment of ₹26.2 crore
- 29 girl hostels constructed at a cost of ₹47 crore lying unoccupied.

कैग रिपोर्ट: खनन, बिजली निगम समेत कई विभागों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

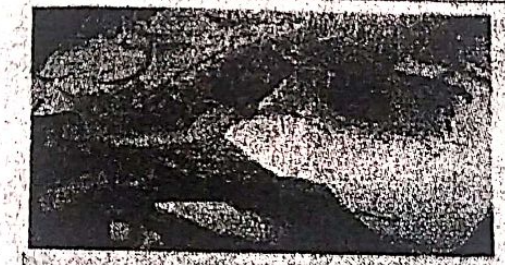
खनन ठेकेदारों ने बदला यमुना नदी का प्रवाह, स्टांप शुल्क के 24 करोड़ फंसे, 1476 करोड़ के राजस्व का भी नुकसान

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

कैग की रिपोर्ट में खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदारों ने खनन में इस कदर मनमानी बरती कि इससे यमुना नदी का प्रवाह ही बदल गया। ठेकेदारों पर आरोप है कि नदी के प्रवाह में बाधा बन गए और नदी का प्रवाह बदल गया।

चयनित रेत और बोल्डर बजरी खदानों के भू-स्थानिक सर्वेक्षण से पता चला है कि खनन योजनाओं में दिए गए खनक स्थलों के को-ऑर्डिनेट साइट निरीक्षण पर दर्शाए को-आर्डिनेट से भिन्न थे। खनन ठेकेदारों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस 24.36 करोड़ रुपए की फीस कम जमा कराई है। कैग रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ कि स्टोर क्रेशर चलाने के लाइसेंसों के नवीनीकरण में विलंब, ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी, अतिरिक्त रॉयल्टी और उस पर ब्याज की कम वसूली, अवसूली के मामले सामने आए हैं। इसके परिणामस्वरूप 1476.21 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। खनन के प्रति सरकार की लापरवाही उजागर हुई है। सरकार ने खदान और खनिज विकास, पुर्नउद्धार पुनर्वास निधि में अपने हिस्से के 17.70 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए। जबकि 4.61 करोड़ रुपए का ब्याज क्रेडिट नहीं किया।

खदान और खनिज विकास की राशि न विभाग और न ठेकेदारों ने करवाई जमा



48 ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं

विभाग ने खदान और खनिज विकास एवं पुनर्वास निधि में 49.30 करोड़ रुपए की राशि जमा न कराने वाले 48 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इन ठेकेदारों की तरफ 17.44 करोड़ रुपए भी बकाया था। यही नहीं संचित राशि 808.21 करोड़ रुपए जमा न कराने वाले 84 ठेकेदारों में से सरकार ने 69 के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इन पर करीब 347 करोड़ रुपए ब्याज के बकाया है।

माल ढोने वाले वाहन मालिकों ने नहीं दी राशि

रिपोर्ट में उल्लेख किया कि वर्ष 2016-17 के दौरान माल ढोने वाले 1584 वाहन मालिकों ने माल कर जमा नहीं कराया। इनसे 1.62 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की गई। इन पर 61.33 लाख रुपए ब्याज भी बकाया था। यही नहीं माल ढोने वाले 1305 वाहन मालिकों ने 2015-16 व 2016-17 के दौरान टोकन टैक्स जमा नहीं कराया, इससे 18.42 लाख रुपए की वसूली नहीं हुई। इन पर 36.84 लाख रुपए की पेनल्टी भी बकाया थी।

ईंट-भट्ठों के 181 मामलों में रॉयल्टी जमा नहीं: *रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 4139 ईंट भट्ठा स्वामियों में से 181 मामलों में रॉयल्टी एवं अतिरिक्त रॉयल्टी के तौर पर 0.53 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए। इन पर 0.24 करोड़ रुपए ब्याज भी बकाया था।*

लापरवाही: कम सिक्योरिटी के चलते निगम पर पड़ी दोगुनी मार

बिजली वितरण कंपनियों की लापरवाही के चलते निगमों को दोहरा नुकसान हुआ है। उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अग्रिम उपभोग राशि नहीं जमा करवाने से 1050 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। निगम उपभोक्ताओं से 935 करोड़ 91 लाख रुपए अग्रिम राशि के तौर पर वसूलने में भी विफल रहे। बिजली निगमों को अतिरिक्त ब्याज के तौर पर 122 करोड़ 5 लाख रुपए की चपत लगी। यह खुलासा विधानसभा में रखी कैग रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में 2013 से 2016 के दौरान निगमों को सी एंड टी लॉस के चलते 2703 करोड़ 69 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। निगमों ने सी एंड टी लॉस में सुधार किया। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेशों के विरुद्ध महिला उपभोक्ताओं को 2005-06 और 2017-18 में 14 करोड़ 40 लाख रुपए की रियायत दी गई। सरकार ने आयोग की मंजूरी के बिना रेट कम किय तो इससे भी 6 करोड़ 41 लाख रुपए का नुकसान हुआ।

कृषि : कम वसूली से 15 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान

कृषि पंप सेट मीटर वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभारों एवं नियत प्रभारों की कम वसूली हुई। मीटर किराए के कम प्रभारण के कारण निगमों को 15 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। मार्च-2018 तक बिजली कंपनियों ने एचईआरसी द्वारा निर्धारित संग्रहण दक्षता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया था। यही नहीं मार्च-2014 में यह बकाया 4460 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो अब मार्च-2018 में बढ़कर 7332 करोड़ 70 लाख पहुंच गया। कंपनी ने बिजली के ट्रांसफार्मर के तेल की खरीद ओपन टेंडर की बजाय लिमिटेड टेंडर से की। इससे निगम को 5 करोड़ 34 लाख रुपए अतिरिक्त खर्चने पड़े। निगम द्वारा खरीदे गए बिजली उपकरणों का इस्तेमाल भी इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि एनएबीएल सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट हासिल करने में देरी की गई। इससे कंपनी का 198 करोड़ 54 लाख से अधिक का सामान इस्तेमाल नहीं हो पाया।

बजट नहीं किया खर्च

हिसार कृषि विवि में मिलीं खामियों से योग्यता हुई कमजोर

कैग की रिपोर्ट ने हिसार के चौधरी चरण कृषि विश्विवद्यालयों की खामियां भी उजागर की हैं। जिस प्रकार खामियां सामने आई हैं, उससे विश्विवद्यालय अपने उद्देश्य प्राप्त करने की योग्यता को कमजोर किया है। 3.12 करोड़ रुपए अनुदान में मिले विवि ने खर्च ही नहीं किए। इसी प्रकार यहां पर पीजी डिप्लोमा 40 और एमबीए कोर्स में 56 फीसदी के बीच रही है। हाल यह है कि 55 प्रतिशत शैक्षणिक स्टाफ और 41 प्रतिशत गैर शैक्षणिक स्टाफ की कमी मिली। दो हॉस्अलों का रखरखाव खराब मिला। विशेषज्ञ वैज्ञानिक न होने की वजह से टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला सक्रिय नहीं है। 100 अनुसंधान परियोजनाओं में केवल 49 ही पूरी हुई मिली। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रामधन सिंह बीज फॉर्म की केवल 44 प्रतिशत और 50 प्रतिशत खेमी योग्य भूमि का प्रयोग भी नहीं किया गया।

TOI

THE TIMES OF INDIA, CHANDIGARH | MOHALI | PANCHKULA | PATIALA | AMBALA
WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2019

Lax mining dept let contractors rob it of ₹1,476cr, reveals CAG

Report Says No Or Delayed Payment Led To Losses

Manvir.Saini@timesgroup.com

Chandigarh: Unscrupulous contractors took benefit of the lax management of the Haryana mining department and caused revenue loss of Rs 1,476.21 crore to the state in the financial year ending March 2018 alone, the Comptroller and Auditor General (CAG) has revealed.

This is sure to cause embarrassment to Manohar Lal Khattar-led BJP government, which fought the recent elections on the plank of good governance and barely managed to retain its hold on the power. Nayab Singh Saini, who held the mining and geology department portfolio in the last government, was elected as Kurukshetra MP in May. He was MLA from Naraingarh assembly constituency, one of the most mineral-rich areas of the state.

The CAG report, which pointed out how delayed and even non-payment of security deposits and royalty resulted in the loss to state exchequers, was tabled in the Haryana assembly on Tuesday.

"Management and monitoring of the funds by the department was deficient. Delays in renewal of licences to operate stone crushers, cases of short or non-recovery of royalty, additional royalty and interest thereon from the brick kiln owners were also noticed. These resulted in a loss of Rs 1,476.21 crore revenue," the report reads.

A total of 77 out of 95 contractors executed the agreements after delays ranging between five and 891 days. The CAG report says that nine contractors did not execute the agreements at all. It quantified such loss at Rs 808 crore, along with the penal interest of Rs 347.63 crore.

The opposition had accused former ministers and their kin of cornering mining licences in Yamunanagar, Panchkula, Charkhi Dadri, Mahendergarh and other districts of Haryana.

CAG pointed out that besides defaulting on payment of bid money or security, certain contractors did not even executed the contract deeds with the government which resulted into the loss of stamp duty worth Rs 23.29 crore.

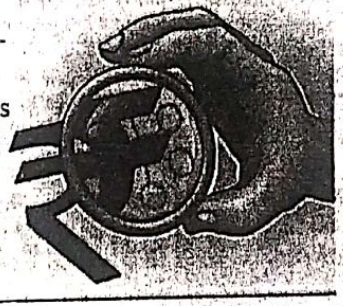
The firms that defaulted in executing the deed too were linked to influential politicians of the state and their companies are also accused of over exploiting the allotted zones for the purpose of mining of minor and major minerals.

According to norms, contractors or lessees are required to deposit security equal to 25% of the annual contract money or dead rent, out of which 10% shall be deposited as initial bid security at the fall of hammer and the balance 15% bid security shall be deposited before starting mining operations or before expiry of the period of 12 months from the date of issue of Letter of Intent, whichever is earlier.

CAG report says 59 contractors deposited balance bid security of Rs 132.02 crore with delay ranging between three and 854 days, while 11 contractors did not deposit the balance bid security of Rs 29.29 crore at all. The report also points out that the department not only failed to recover money but also did not take action against any of the defaulting contractor.

OTHER ISSUES IN REPORT

- Registering authorities incorrectly assessed 100 sale deeds of plots with an area less than 1,000 sq yards falling within municipal limits at rates fixed for agricultural land instead of residential land. This resulted in short levy of stamp duty and registration fees of ₹2.45 crore
- The registration authorities misclassified conveyance on sale as release deeds and levied stamp duty and registration fees of just ₹10,920 instead of ₹1.71 crore as per collector rate
- Irregular remission of stamp duty in 53 instruments of transfer deeds in favour of persons other than blood relations resulted in loss of revenue of ₹88.78 lakh to the state exchequer



28/11/2019

पंजाब केसरी

अवैध खनन हरियाणा प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला: कु. शैलजा

चंडीगढ़, 27 नवम्बर (बंसल): कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कु. शैलजा ने विधानसभा में रखी गई कैग रिपोर्ट में उजागर हुए खनन घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश में अवैध खनन को हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने इस घोटाले में खनन माफियाओं के साथ सरकार के लोगों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया।



उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियमों के विरुद्ध खनन को कैग ने उजागर किया है, साथ ही यह भी बताया है कि कई जगह खनन माफिया ने नदी का बहाव तक को बदल दिया है। खनन विभाग की लापरवाही के कारण सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। कैग ने खनन के लिए आबंटित स्थलों का निरीक्षण भी किया है, जिसमें पाया गया कि आबंटित स्थानों के बजाय माफिया ने दूसरी जगह खनन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए खनन पर आई कैग रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि सरकार भी इस अवैध खनन के खेल में भागीदार है। इस रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि किस तरीके से खनन माफिया और ठेकेदारों ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और सरकार चुप्पी साधे रही।

यमुनानगर से होडल तक चल रहा खेल

कुमारी शैलजा ने कहा कि अवैध रेत खनन का यह खेल यमुनानगर से लेकर होडल तक चल रहा है। इस सरकार में अरावली की पहाड़ियों में भी जमकर अवैध खनन किया गया है। वर्ष 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई उसी के बाद यह अवैध खनन का काला खेल शुरू हो गया था और यह निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में अवैध खनन कर रहे माफियाओं ने पुलिस और अफसरों की मौजूदगी में अवैध खनन का विरोध कर रहे लोगों पर हमला किया, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे रहा।

उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2017 में भिवानी के डाडम पहाड़ में खनन कार्य में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद खनन पर रोक लगानी पड़ी थी। फरीदाबाद में अरावली श्रृंखला में निर्माण कार्यों की छूट देकर सरकार ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवेहलना की थी, बल्कि अरावली में अवैध निर्माणों का रास्ता भी खोल दिया। इस मामले में सरकार की काफी किरकरी भी हुई और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस सबके के बावजूद अरावली में आज भी मिलीभगत से अवैध खनन और निर्माण जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कैग रिपोर्ट में बिजली वितरण कंपनियों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए के नुक्सान का भी जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि इस सरकार की प्रदेश के हितों के लिए न तो कोई नीति है और न ही कोई नीयत। कु. शैलजा ने ने मांग की कि सरकार खनन के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करे और इस घोटाले की जांच हाईकोर्ट की देखरेख में करवाई जाए।

Scanned by CamScanner

The Tribune - 28/11/2019

CAG: Backward areas lag in student-teacher ratio

BHARTESH SINGH THAKUR
TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, NOVEMBER 27

Despite having online teacher transfer policy since 2016, the student-teacher ratio is poor in backward districts, says the Comptroller and Auditor General (CAG).

The ideal student-teacher ratio is 30:1 as per the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA). The CAG's report for the period ended March 31, 2018, was submitted in the Assembly on Tuesday.

"The student-teacher ratio is poor (between 36.2 and 44) in backward regions, especially Nuh, Fatehabad and Sirsa districts, which are special focus districts under the RMSA," read the CAG report.

On the other hand, it was between 17.08 and 20.79 in Rohtak, Jhajjar and Panchkula. The CAG report said fewer teachers were deployed in backward regions and more in Rohtak, Jhajjar and Panchkula.

1 TEACHER FOR...

Nuh	44 STUDENTS
Y'nagar	37.55
Fatehabad	36.29
Sirsa	34.98
Palwal	34.22
P'kula	20.79
Jhajjar	18.7
Rohtak	17.08

The CAG report said the Teachers Transfer Policy 2016 was fair and transparent, but failed to ensure equitable distribution.

In Ambala, Fatehabad, Nuh, Sirsa and Yamunanagar, 4,013 teachers were posted against a sanctioned strength of 8,084. There were over 50 per cent vacancies in these districts, more than the average of 38 per cent vacancies in the state, read the CAG report.

Despite 2,128 sanctioned posts, no PGT, trained to teach up to Class XII, was posted in 325 schools (nearly 10 per cent). A total of 77 schools had student-teacher ratio of more than 100.

Of the sanctioned strength of 11,333 in science subjects, 5,698 were filled and 5,635 vacant. Vacancies in science subjects ranged between 71 per cent and 85 per cent in backward areas of Fatehabad, Nuh and Kaithal. There were fewer vacancies in Panchkula, Rohtak, Rewari, Mahendragarh and Gurugram, ranging between 21 per cent and 34 per cent, according to the CAG report.

Compared to the ideal ratio of 5:1 for special educators to children with special needs, it remained between 16 and 33 during 2013-18.

Scanned by CamScanner

दैनिक जागरण — 29/11/2019

www.jagran.com

हरियाणा

22.75 करोड़ में बनना था बहुउद्देशीय हॉल, 21.5 करोड़ तो नींव में ही लग गए

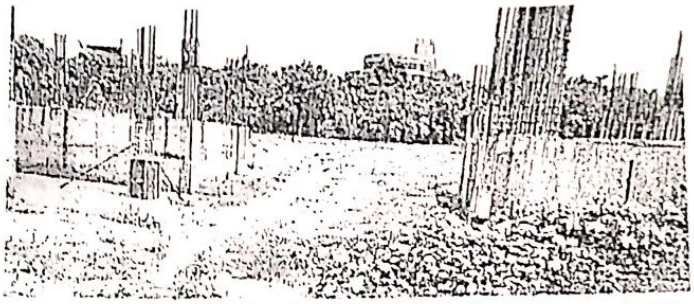
गुरुग्राम में ताऊ देवी लाल खेल परिसर में इनडोर मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण में गड़बड़ी

सुधीर तंवर • चंडीगढ़

गुरुग्राम में ताऊ देवी लाल खेल परिसर में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। सरकारी स्तर पर हॉल बनाने के लिए 22.75 करोड़ रुपये के बजट की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। ठेकेदार ने 21.50 करोड़ रुपये खर्च भी दिखा दिए, लेकिन भरी गई सिर्फ नींव। काम पूरा होने की निर्धारित तिथि के तीन साल बाद भी काम अधूरा था।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कराए निर्माण कार्य में गड़बड़झाले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संरचनात्मक डिजाइन और विस्तृत अनुमान तैयार किए बिना ही प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। निर्माण कार्य में देरी से इनडोर स्टेडियम की लागत भी 15 करोड़ रुपये बढ़ गई। इसके अलावा नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्य की नई मदों को जोड़कर परियोजना लागत में बढ़ोतरी की गई। कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि के तीन वर्षों से अधिक समय बीतने और 20.39 करोड़ रुपये खर्चने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा रहा।

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबंध में 9.54 करोड़ से लेकर 52.15 करोड़ रुपये तक की अनियमित बढ़ोतरी की गई। निविदा आमंत्रित किए बिना अतिरिक्त सड़कों के निर्माण का काम ऐसे ठेकेदार को दिया गया, जो अयोग्य था। निर्माण पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा भी तय नहीं की गई। इसका फायदा उठाकर ठेकेदार ने दो वर्षों में केवल छह फीसद सड़क का निर्माण किया। 2.60 करोड़ की निष्पादन गारंटी नहीं मिलने से सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ।



गुरुग्राम में ताऊ देवी लाल खेल परिसर में बहुउद्देशीय हॉल के लिए निर्माणाधीन भवन • जागरण

कैग ने उठाए सवाल

- डिजाइन और विस्तृत अनुमान तैयार किए बगैर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
- काम पूरा करने की तय तारीख के तीन साल बाद भी काम अधूरा

गुरुग्राम और सोनीपत में लटकी जलापूर्ति की परियोजनाएं : भूमि का अधिग्रहण किए बगैर ही निर्माण कार्यों का आवंटन और परियोजनाओं के लिए बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण गुरुग्राम और सोनीपत में मुख्य जलापूर्ति परियोजनाएं अपूर्ण रहीं। इससे परियोजना पर खर्च किए जाने वाले 300.76 करोड़ रुपये अनुपयोगी रहे। पाइपों को बिछाए बगैर ही भुगतान से 26.35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पाइप लाइन बिछाने के लिए ठेकेदार द्वारा 8.75 एकड़ भूमि खरीदने के लिए अनियमित प्रावधान वाले दोषपूर्ण डिटेल्ड नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के कारण सोनीपत में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का अपेक्षित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

जागरण की खबर पर विजिलेंस ने की थी जांच

जासं, गुरुग्राम: खिलाड़ियों को कई खेल सुविधा देने की मकसद से प्रदेश सरकार ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम मे बहुउद्देशीय हॉल बनवाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसे तैयार कराने की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को सौंपी गई थी। निर्माण में गड़बड़झाले की खबर दैनिक जागरण ने आरटीआइ से मिली जानकारी के आधार पर प्रकाशित की थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। वर्ष 2018 में प्रोजेक्ट को गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण के हवाले कर दिया गया था। वर्ष 2015 में गुरु नानक इंजीनियरिंग सर्विस को 13.5 करोड़ रुपये का टेंडर अलॉट कर 15 माह में निर्माण करना था। इसके बाद 2016 में यह राशि बढ़ाकर 22 करोड़ रुपये कर दी गई लेकिन निर्माण केवल डीपीसी तक सीमित रहा, जबकि रकम अदा कर दी गई थी।

Scanned by CamScanner

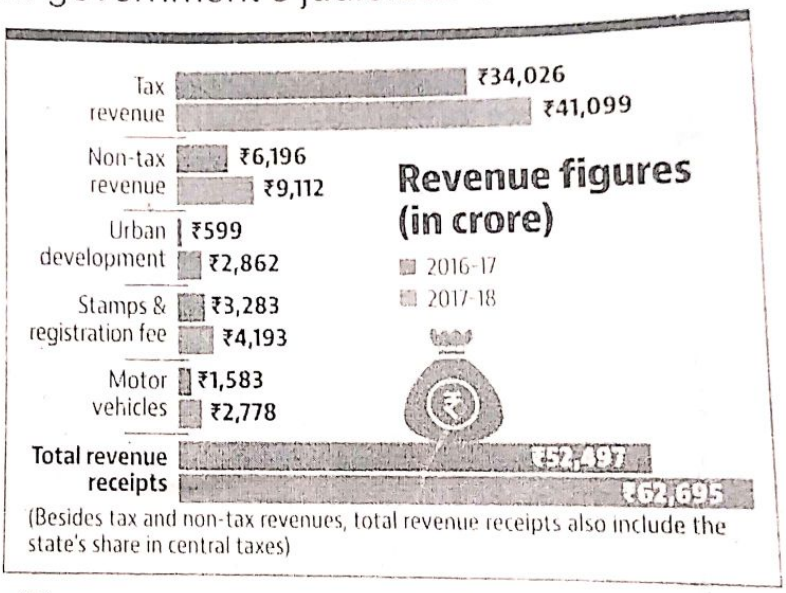
Hindustan Times - 29/11/2019

280

Haryana registered up to 21% tax revenue growth from 2013-18

CAG REPORT Officials say 'sharp increase' due to urban development and state government's judicious decisions

Pawan Sharma
pawan.sharma@hindustantimes.com



CHANDIGARH: The Comptroller and Auditor General (CAG) of India's latest revenue sector report on Haryana for the 2017-18 fiscal highlights a "sharp increase" in tax and non-tax revenues, pointing towards fiscal prudence by successive governments in the state.

The growth of tax revenue over the years is 8 to 21%, says the report that was presented in the Vidhan Sabha on Tuesday during the special session to observe the 70th Constitution Day. It says that under urban development there was a "sharp increase" in revenues. From ₹599 crore generated by the urban development department in 2016-17, it went up to ₹2,861.45 crore in 2017-18—a net rise of ₹2,262 crore in a year.

Senior officials attribute this rise to factors such as urban development and one of the state government's decisions. Since April 1, 2017, the government started depositing the money recovered under the external development charges (EDC) from the licencees in major receipts head of the town and country planning (TCP) department.

Earlier, the EDC recovered by TCP department from the licencees used to be transferred to the Haryana Shahri Vikas Pradhikaran (HSVP) being the nodal agency of the state government for execution of external development works in the urban estates of Haryana.

Similarly, the state registered growth in revenue from the stamps and registration fees.

The CAG report says: "During the last five years, the stamp and registration fee has increased to ₹4,192.49 crore in 2017-18 as against ₹3,282.64 crore in 2016-17."

As per the auditor, the reason behind the state generating ₹910 crore more than the previous fiscal was due to increase of transactions of immovable property.

Similarly, under the taxes on motor vehicles the actual receipts increased by Rs 1194 crore in a year from ₹1,583.06 crore in 2016-17 to ₹2,777.57 crore in 2017-18.

In what is a pat on the back of the state transport department the CAG says this rise in receipts was also due to "intensive checking of overloaded vehicles on road."

Also, the taxes on goods and passengers registered impressive growth. The CAG says actual receipt under this head in 2017-18 was ₹2,317.47 crore against ₹594.59 crore in 2016-17. This steep rise of ₹1,723 crore in a year, the CAG says, became possible after the state on 22 June 2017 introduced Haryana one-time settlement scheme for recovery of outstanding dues.

In 2017-18, Haryana government raised ₹50,212 crore as revenue, which was 80% of the total revenue receipts.

The balance 20% of the receipts during 2017-18 came from the Centre as State's share of net proceeds of divisible Union taxes and grants-in-aid.

The tax revenue increased from ₹25,566.60 crore in 2013-14 to ₹41,099.38 crore in 2017-18.

Scanned by CamScanner

Times of India — 29/11/2019

278

State urban planner staring at bankruptcy: CAG report

'Has Shown -ve Growth In Last 5 Years'

Manvir.Saini@timesgroup.com

Chandigarh: Haryana's biggest public sector real estate entity, the Haryana Shahri Vikas Pradhikaran (HSVP), which has been ruling the realty sector in the state since 1977, has charted negative growth over 5 years, and is now rolling towards bankruptcy. The CAG (Comptroller and Auditor General) report submitted during the special session of Haryana Assembly on Tuesday has indicated this.

The report contains a complete chapter on the negative growth since 2013 and elaborates on how expenses have exceeded revenue recovery. It also contains details of laxity by HSVP bureaucrats in initiating recoveries from defaulters, including occupant owners of commercial properties and liquor vends as well as leasee petrol stations.

HSVP has also "forgotten" the allottees of HSVP commercial sites who have not deposited 25% of the basic cost of property. There are over 3,100 such commercial properties in main urban estates of Panchkula, Karnal, Sonipat Gurugram and Faridabad where arrears worth over Rs 1000 crore are outstanding against the allottees, sources said. This has been endorsed by the CAG report.

Non-initiation of action against defaulters and inadequate efforts for auction of unallotted properties in developed sectors have hampered revenue generation by HSVP. This was because non-reconciliation of allottee ledgers led to non-detection of fraud and no perspective plan for time-bound development of acquired land.

Further, delay in recovery of enhanced land compensation, non-recovery of external development charges, continuance of business in resumed properties, non-recovery of water and sewerage charges and outstanding rent on leased property impacted revenue generation by HSVP.

According to the CAG report, the receipts in HSVP have decreased from Rs 5,234 crore in 2013-14 to Rs 4,219 crore in 2017-18. This is mainly due to dip in receipt of external development charges (EDC) from town and country planning department (TCPD), delays in recovery of land enhanced compensation and decline in sale proceeds of residential and commercial plots.

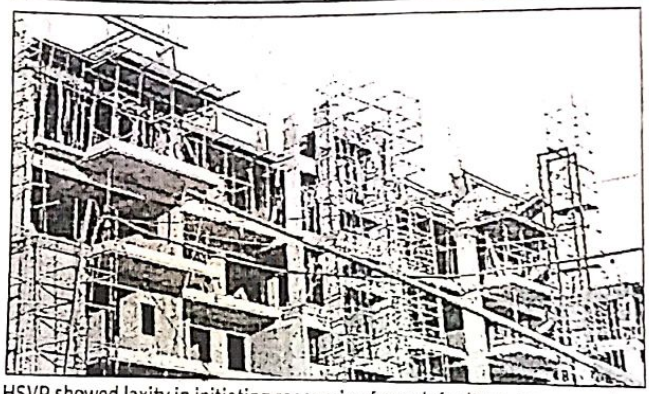
To assess whether the realisable revenue is being collected efficiently and is accounted for in a proper manner, records of 5 out of 18 estate offices for 2015-18 were scrutinised during December 2017 to April 2018 with audit focus on revenue earning streams directly under control of HSVP. Audit has used the data (obtained in December 2017) from Plot and Property Management (PPM)109 software, used for management of plots and property falling under HSVP.

What pushed HSVP into bankruptcy

Default of commercial plots: CAG team had taken samples of records from the offices of estate officers in Gurgaon, Ambala, Sonipat, Faridabad and Panchkula

WHAT THE SCRUTINY HAS FOUND

- As many as 3,177 plot allottees have not deposited mandatory 25% of the bid money
- **Default by liquor vends:** 11 liquor vends in Gurgaon had defaulted payment of over ₹11 crore, the outstanding in monthly rent
- **Dues yet to be paid by fuel stations:** The case is similar in petrol station sites as well. They are still in operation though the dues have crossed ₹1.10 crore
- **Delayed recovery of enhancement:** HSVP has defaulted recovery of arrears worth hundreds of crores from allottees in Panchkula, Karnal, Sonipat, Gurgaon, Rewari and new urban estates



HSVP showed laxity in initiating recoveries from defaulters, says report

Hry registers 30.54% GST hike in Jul-Oct

TIMES NEWS NETWORK

Chandigarh: Haryana has registered a significant growth rate of 30.54%, which is highest in the country, under goods and services tax (GST) collection from July to October during the current financial. An amount of Rs 6,930 crore has been collected as GST during this period.

This was stated in a meeting presided over by chief minister Manohar Lal Khattar to review the functioning of excise and taxation department here.

The CM said with a view to check tax evasion and to improve GST collection, a state-wide registration drive should be launched for the registration of left out firms and also to cancel the registration of fake firms. Under the GST regime, a business whose turnover exceeds Rs 40 lakh is required to register as a normal taxable person. He also directed the department to depute officers, who would personally visit atleast 50 people in different districts that are registered dealers, but did not file return so that reason for the same could be ascertained and accordingly steps could be taken.

It was stated that in order to check evasion of tax under the GST, the sale of registered dealers was reviewed regularly by the tax research unit (TRU) of the department by identifying any mismatch between the inward and outward supply and tax paid. It was also stated that 6,160 taxpayers had been identified, who contribute nearly 80% of the total state GST revenue. A special drive has been launched to pursue them to pay tax regularly and as a result of this, return has been significantly increased during the last four months.

Scanned by CamScanner

AMBALA • SUNDAY • 1.12.2019

'5 हजार करोड़ से ज्यादा का

हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाए सरकार, राज्यसभा

■ **घोटाले में सफेदपोश, अफसरशाही और माफियाओं के गठबंधन का लगाया आरोप**

चंडीगढ़ 30 नवम्बर (पांडेय) : प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कैग रिपोर्ट के खुलासे तहत खट्टर सरकार पर खनन घोटाले का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की है।

कुमारी शैलजा व रणदीप सुर्जेवाला ने कहा कि पिछले 18 महीनों से खट्टर सरकार इस घोटाले पर आंखें और आंखें मूंदकर बैठी है जबकि सरकार के राजस्व पर करीब 5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस घोटाले में या तो सरकार की मिलीभगत है या फिर सरकार जानबूझकर इसे इग्नोर



पत्रकारों से बातचीत करते कुमारी शैलजा व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुर्जेवाला।

कर रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या खनन माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इतना घोटाला बिना सरकार के संज्ञान के नहीं हो सकता है।

शैलजा ने इस मामले को राज्यसभा में उठाने के लिए भी नोटिस दिया है। चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि इस घोटाले में नदियों का रास्ता बदला गया और इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है।

सरकार, राज्यसभा में मामला उठाने का शैलजा ने दिया नोटिस

खुली लूट और पूरी छूट के सिद्धांत पर पनपा खनन माफिया : रणदीप



कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुर्जेवाला। (केवल कृष्ण)

उठाने के लिए भी नोटिस दिया है। चंडीगढ़ प्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते होंने कहा कि इस घोटाले में नदियों का ना बदला गया और इससे पर्यावरण को भारी नुक्सान हुआ है।

मंत्री : सुर्जेवाला

मंत्री मनोहर लाल खट्टर जिसे छूते है लन, हुडा विभाग का नाम तो सरकार स.डी.पी. कर दिया लेकिन उस पर

रणदीप सुर्जेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार में 'खुली लूट-पूरी छूट' के सिद्धांत पर खनन माफिया पनप रहा है। कैग रिपोर्ट ने खट्टर सरकार व खनन ठेकेदारों की मिलीभगत की पोल खोलकर रख दी है। पिछले 4 वर्षों से हरियाणा में खनन माफिया व सरकार का गठजोड़ कई बार उजागर हुआ है। यमुना नदी पर गैर-कानूनी बांध बना रेत, रोड़ी, पत्थर का अवैध खनन भाजपा सरकार की नाक तले खुलेआम चल रहा है। खट्टर सरकार को यह नहीं मालूम कि सरकार द्वारा बोली लगाई गई, 95 खदानों में कितना खनिज भंडार है, जिसे निकाला जा सकता है। सरकार को नहीं मालूम कि खनिज ठेकेदारों द्वारा कितना खनिज निकाला गया।

खट्टर सरकार के पास निकाले गए खनिज के वजन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार के पास खनिज ठेकेदारों द्वारा निकाले खनिज की ट्रांसपोर्ट (ट्रांसपोर्टेशन) व ट्रांसपोर्ट परमिट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार के पास 95 खनिज खदानों की जांच व निरीक्षण का कोई रिकॉर्ड नहीं। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा सरकार को इन 95 खनिज खदानों से 2,133 करोड़ रुपए सालाना की आय होनी चाहिए।

उधर कैग रिपोर्ट ने पाया कि खनन ठेकेदार दोगुने क्षेत्र में खनन कर राजस्व को चूना लगा रहे हैं अगर इसे सभी 95 खनन क्षेत्रों में लागू किया जाए और यह माना जाए कि तीन चौथाई खनन क्षेत्रों में दोगुने या उससे अधिक क्षेत्रफल में खनन हो रहा है (जैसा कि सैंपल सर्वे में कैग ने दर्शाया है), तो 5000 करोड़ रुपए सालाना से अधिक का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

ठेकेदारों ने सरकारी राजस्व को लगाई 1476.21 करोड़ की चपत

सुर्जेवाला ने कहा कि कैग रिपोर्ट मुताबिक, राहुल सरकार ने 31 मार्च, 2018 तक [illegible] लगाया। सच तो यह है कि भाजपा सरकार ने खनिज ठेकेदारों पर [illegible] भाजपा सरकार खनन ठेकेदारों से मासिक व सिंगल रिपोर्टिंग टैक्स कर 66.74 करोड़ रुपए का [illegible] कि राहुल सरकार की नाक के नीचे खनन ठेकेदार बेखौफ खनन क्षेत्र पर डटे रहे और [illegible] दिया गया, तदनुसार की सीमा बढ़ती गई और वर्ष 2017-18 तक [illegible] गुमथला तहत खनन ब्लॉक के रूप में यह साफ तौर से साबित हुआ कि खनन ठेकेदार [illegible] किए जाने वाले रिजर्व की मात्रा भी 20.34 लाख टन से घटकर 44.22 [illegible]